# कितनी हत्याओं के बाद नगर निगम को सुधारेगी सरकार?

**फ़रीदाबाद ( म.मो. )** सेहतपुर गांव के निकट सीवर के पानी से भरे गड्ढे में गिर कर युवक की मौत के दो दिन बाद ही नगला इन्क्लेव स्थित खुले मैनहोल में गिर कर योगेश नामक युवक की जान तो बच गई लेकिन जबड़ा टूट गया। लोग मरते रहें, जबड़े तुड़वाते रहें क्या फर्क पड़ता है इस बेशर्म सरकार के निगम को?

बीते सप्ताह सेहतपुर गांव के इलाके में कच्ची सड़क के किनारे सीवर से भरे खड्डे में एक युवक ने उस समय अपनी जान गंवा दी जब वह रात की ड्यूटी करके मोटरसाइकिल से घर आ रहा था। क्षेत्र की शिव कॉलोनी नामक इस स्थान पर न तो ढंग के रास्ते हैं और न ही कोई रोशनी की व्यवस्था है। रात के अंधेरे में खड्डे को न देख पाकर युवक उसमें गिर पड़ा। पीछे बैठी पत्नी जो खड्डे के बाहर गिरी थी, वह चिल्लाती हुई खड्डे में कूदी तो जरूर लेकिन अपने पति को ढूंढ नहीं पाई। समझा जा सकता है कि खड्डा 6-7 फीट से अधिक ही गहरा होगा। शोर सुनकर आये लोगों ने जैसे-तैसे दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक युवक की हालत खराब हो चुकी थी।

हरियाणा सरकार की बहुप्रचारित एम्बुलेंस सेवा के नम्बर 112 पर लगातार कई बार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैसे-तैसे युवक को ऑटो में डाल कर बीके अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सड़कें सुरक्षित नहीं, एम्बुलेंस का जवाब नहीं, अस्पतालों में इलाज नहीं उसके बावजूद विकास का ढोल पूरे जोर से पीटा जा रहा है। नंगला इन्क्लेव वाले योगेश के मामले में निगम के एक्सईयन कर्दम से जब पूछा गया तो उनका जवाब था कि मैन होल का ढक्कन लगा दिया गया है। ढक्कन लगा हुआ क्यों नहीं था इसका कोई जवाब नहीं, केवल इतना कहा कि और भी कोई मैनहोल खुला हो तो उसे सूचित करें। उधर योगेश के परिजनों ने पुलिस में केस दर्ज कराने की बात कहीं है। जाहिर है यदि निगम वालों के खिलाफ़ आपराधिक मुकदमें दर्ज हों और उन्हें सजा मिलने लगे तो नागरिकों की जान बच सकती है।

## मिर्जापुर एसटीपी के नमूने आज नहीं बल्कि सदा से ही फेल रहे हैं और आगे भी रहेंगे, निगम अधिकारी कब इनकी परवाह करते हैं

**फ़रीदाबाद ( म.मो. )** हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा न केवल मिर्जापुर बल्कि बादशाहपुर व प्रतापगढ़ स्थित एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) द्वारा शोधित पानी के जब भी कभी नमूने लिये हैं, वे फेल ही पाये गये हैं। सीवेज पानी की बात तो छोड़िये, नगर निगम द्वारा सप्लाइ किये जाने वाले पेय जल के नमूने भी आज तक कभी पास नहीं हो पाये। इस सबके बावजूद नगर निगम भी शहर की छाती पर दनदना रहा है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी।

प्रकाशित खबरों में कहा जा रहा है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर निगम के मुख्य अभियंता को इसके लिये कारण बताओ नोटिस जारी किया है। निगम अधिकारियों के लिये इस तरह के नोटिसों के जवाब देना कोई मुश्किल काम नहीं है। उनकी सारी नौकरी इस तरह के नोटिसों के जवाब देने व काम न करने के बहाने बनाने में बीती है। बोर्ड उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोर्ड तो बोर्ड एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रब्यूनल) ने ही इनका क्या उखाड़ लिया? सुधी पाठक भूले नहीं होंगे कि एक मामले में पूर्व निगमायुक्त अनिता यादव को एनजीटी ने व्यक्तिगत रूप से बुला कर झाड़ा था और 50 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

इसके बावजूद ढाक के वही तीन पात। एनजीटी इन्हें झाड़ता है तो ये वहीं कपड़े झाड़ कर आ जाते हैं। रही बात जुर्माने की तो वह कौनसा इनकी जेब से जाना है, सरकार ने ही देना है और सरकार ने ही लेना है। यह तो केवल जनता को बेवकूफ़ बनाने की कवायद मात्र है। यही स्थिति अब हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की है। उन्होंने नमूने फेल बता दिये और नगर निगम ने मान लिये, बस खत्म हुई बात।

प्रदूषित पानी यूं ही निकल कर यमुना में गिरता रहेगा। यह मसला कोई एक फ़रीदाबाद नगर निगम का नहीं है बल्कि देश भर की निगमों द्वारा लगाये गये सीवेज प्लांटों का यही हाल है। इसी के चलते गंगा व यमुना एक्शन प्लान के तहत अरबों-खरबों खर्च किये जाने के बावजूद दोनों नदीयां बद से बद्तर होती जा रही हैं। समझना मुश्किल नहीं, कारण खुला भ्रष्टाचार है।

# वेतन का खर्च बचा कर अय्याशी करती खट्टर सरकार

**चंडीगढ़ ( म.मो. )** राज्य सरकार के काम-काज को सुचारू ढंग से चलाने के लिये बीसियों वर्ष पूर्व 4 लाख 45 हजार 346 पद स्वीकृत किये गये थे। समय के साथ-साथ राज्य में आबादी एवं काम-काज में बढोतरी के चलते इन पदों में भी बढोतरी होनी चाहिये थी। पदों को बढाना तो दूर रहा, इनमें से 1 लाख 82 हजार 497 पद रिक्त पड़े हैं। देश में काम करने वाले दक्ष लोगों की कोई कमी न होने के बावजूद सरकार ने इन पदों को केवल इस लिये खाली रखा हुआ है ताकि वेतन पर होने वाला खर्च बचाया जा सके और बचे हुए धन से सरकार की अय्याशियां चलती रहे।

कहने की जरूरत नहीं कि जिस मशीन में से आधे पूर्जे ही गायब कर दिये जाये तो वह मशीन कैसे चल पायेगी? कोई भी सरकार अपने विभागों का सर्जन और उनमें कर्मचारियों की बहाली इसलिये नहीं करती कि लोगों को रोजगार मिल जाये। विभागों का सर्जन व कर्मचारियों की बहाली तो केवल इस लिये की जाती है कि सरकर रूपी मशीनरी बिना लड़खड़ाये सही ढंग से चल पाये। रोजगार तो एक प्रकार का बाई प्रोडक्ट है जो स्वत: निकल आता है। परन्तु इस सरकार को अपनी मशीन को चलाये रखने की कोई चिन्ता नहीं।

गतांक में राज्य के कुछ प्रमुख विभागों- शिक्षा, चिकित्सा, ईएसआई चिकित्सा आदि का विवरण प्रस्तुत किया गया था। इस बार प्रमुख विभाग पुलिस है। इसमें कुल स्वीकृत पदों की संख्या 78306 है, जिसमें से 53328 पद भरे हुए हैं, यानी कि

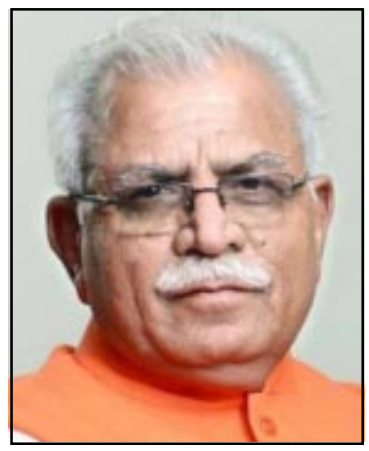

शेष 24959 रिक्त पड़े हैं। विदित है कि नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा के लिये बनाये गये इतने महत्वपूर्ण महकमे में जब इतनी बड़ी संख्या रिक्त पदों की होगी तो उनके भरोसे नागरिक कितने सुरक्षित रह पायेंगे? हां, राजनेताओं एवं प्रभावशाली सम्पन्न लोगों ने जरूर अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिये पुलिस बल के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा रखा है। दूसरी ओर काम के बढ़ते बोझ की वजह से पुलिसकर्मी तरह-तरह की शारीरिक व मानसिक बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं।

खेती-बाड़ी राज्य की अर्थ व्यवस्था की रीढ है। राज्य की बहुसंख्या इससे जुड़ी हुई है। कोरोना के दौरान जब जीडीपी शुन्य से भी नीचे चली गई थी तो खेती-बाड़ी ही एक मात्र धंधा ऐसा था जिसमें जीडीपी को काफी हद तक बचा कर रखा। इसके लिये बने कृषि विभाग में स्वीकृत पदों की संख्या मात्र 4950 है जिसमें से 2663 पद रिक्त पड़े हैं। इसी प्रकार कृषि से जुड़े सिंचाई विभाग में कुल 18996 स्वीकृत पदों के स्थान पर केवल 9039 पद भरे हुए हैं, शेष 9951 पद खाली हैं। इससे सिद्ध होता है कि कृषि एवं सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विभागों के प्रति सरकार कितनी उदासीन है।

राज्य की कमाई का एक महत्वपूर्ण विभाग है परिवहन। इस के लिये सरकार ने 24371 पद स्वीकृत कर रखें हैं जो विभाग की बसों को नियमित एवं सुचारू ढंग से चला कर प्रति दिन सरकार को करोड़ों रुपये कमा कर दे सकें। लेकिन निकम्मी व लापरवाह सरकार ने इन पदों में से 8579 पद रिक्त रखे हुए हैं। अब समझ लीजिये कि परिवहन विभाग सरकार को क्या कमा कर देगा?

लोकल ऑडिट विभाग, बेशक छोटा सा ही है लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। इसका काम सरकार के विभिन्न विभागों के बही-खातों पर नजर रखनी होती है। इसके लिये कुल 652 पद स्वीकृत हैं और इनमें से भी 342 पद खाली पड़े हैं। अब समझ लीजिये कि सरकार के किस विभाग में कहां-कहां कितना-कितना घोटाला व गबन हो रहा है, कोई पूछने वाला नही, किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं। कर दाता का धन लुट रहा है तो लूटता रहे खट्टर साहब ने तो वेतन के करोड़ों रुपये बचा ही लिये। अंग्रेजी में कहावत है 'पैनी वाइज, पाऊंड फुलिश' यानी दमड़ी बचानी है चाहे रुपया खर्च हो जाये।

## निष्ठुर सरकार मस्त, पैसा देने के बावजूद मज़दूर त्रस्त

# ईएसआई अस्पताल में ऑपरेशन के लिये तीन महीने का इन्तजार

**फ़रीदाबाद ( म.मो. )** एनएच तीन स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जरूरत से आधे स्टाफ के बावजूद यहां 120 प्रतिशत ऑकुपेंसी है और ओपीडी में करीब 4500 मरीज़ प्रति दिन आ रहे हैं। सरल भाषा में 600 बिस्तरों के इस अस्पताल में करीब 750 मरीज़ भर्ती रहते हैं। वार्डों में अतिरिक्त बेड लगाने पड़ते हैं।

अस्पताल की कार्यकुशलता एवं स्टाफ़ की मेहनत व लग्न के चलते आ रहे बेहतर परिणामों को देखकर पूरे एनसीआर व हरियाणा भर से मरीजों को यहां रैफर किया जा रहा है। जाहिर है ऐसे में अस्पताल का कार्यभार कई गुणा बढ़ जाना स्वाभाविक ही है। जहां फ़रीदाबाद क्षेत्र में बीमाकृत मज़दूरों की संख्या करीब 6 लाख है वहीं अकेले गुड़गांव क्षेत्र में ऐसे मज़दूरों की संख्या करीब 20 लाख है। शेष हरियाणा व एनसीआर क्षेत्रों की संख्या अलग से है।

विदित है कि गुड़गांव में बीते बीसियों साल से मात्र 100 बेड का तथा मानेसर में 50 बेड का अस्पताल है। जाहिर है ऐसे में गुड़गांव वालों को भी फ़रीदाबाद का यही अस्पताल नजर आता है। न केवल गुड़गांव के बल्कि दिल्ली से भी मरीजों को यहां रैफ़र कर दिया जाता है। इन हालात में ऑपरेशन के लिये मरीजों को तीन-तीन महीने की तारीख नहीं मिलेगी तो और क्या मिलेगा? बीते सप्ताह हर्निया से पीड़ित दिनेश को मानेसर से यहां रैफर कर दिया गया। यद्यपि पीड़ित को तुरंत ऑपरेशन की जरूरत थी लेकिन अस्पताल में लगी लम्बी लाइनों के चलते उसे तीन माह की तारीख दे दी गई। यह भी कोई जरूरी नहीं कि तीन माह बाद भी उसका नम्बर आ ही जायेगा।

**ऐसे में पीड़ित दिनेश को सारा दोष अस्पताल के डॉक्टरों एवं प्रबन्धन का नजर आता है। हर महीने अपने वेतन से करीब 600 रुपये ईएसआई कार्पोरेशन को देने के बावजूद, जरूरत पड़ने पर उसे ठेंगा दिखा दिया गया है। अब यदि उसके पास पैसों का कुछ जुगाड़ बना तो वह किसी निजी अस्पताल में अपना इलाज करा लेगा अन्यथा मरना-जीना राम भरोसे।**

ईएसआई कॉर्पोरेशन द्वारा मज़दूरों के साथ किये जा रहे इस क्रूर मजाक की गहराई नापने की कोशिश न करके मज़दूर केवल अस्पताल के डॉक्टरों आदि पर अपनी भड़ास निकाल कर शान्त हो जाते हैं। उन्हें समझना चाहिये कि कार्पोरेशन में सरकार व मालिकान के नुमाइंदों के अलावा मज़दूर संगठनों के नुमाइंदे भी होते हैं। लेकिन इन नुमाइंदों की नुमाइंदगी केवल नेतागिरी तक ही सीमित रहती है। मज़दूर हितों के लिये सरकार से लड़ने-भिड़ने की उन्हें कोई जरूरत महसूस नहीं होती।

गुड़गांव क्षेत्र में 20 लाख ईएसआई कवर्ड मज़दूर होने के बावजूद इसी साल फरवरी में केन्द्रीय श्रममंत्री भूपेन्द्र सिंह यादव ने मानेसर में साढे सात एकड़ के प्लॉट पर 500 बेड के एक अस्पताल का शिलान्यास किया है। तालियां बजाने व अपनी पीठ थपथपाने के लिये हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर व श्रममंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे।

यहां समझने वाली बात यह है कि फ़रीदाबाद का मेडिकल कॉलेज अस्पताल 30 एकड़ के पलॉट पर बना है। मरीजों की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए इसके विस्तार पर विचार किया जा रहा है। इसके बावजूद भी नेताओं की समझदानी में यह बात नहीं आई कि साढे सात एकड़ के प्लॉट पर बनने वाला 500 बेड का अस्पताल इस क्षेत्र की जरूरतें कैसे पूरी करेगा?

दरअसल हरियाणा सरकार के इस प्लॉट का कोई ग्राहक तो था नहीं, इसलिये इसे ईएसआई कार्पोरेशन के मत्थे मढ़ कर खट्टर ने 120 करोड़ रुपये खरे कर लिये, अस्पताल तो बनेगा जब बनेगा।